

क

#### :: आयुक्त (अपील्स) का कार्यालय, वस्तु एवं सेवा करऔर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क:: O/O THE COMMISSIONER (APPEALS), GST & CENTRAL EXCISE,

द्वितीय तल, जी एस टी भवन / 2nd Floor, GST Bhavan, रेस कोर्स रिंग रोड, / Race Course Ring Road,



सत्यमेव जयते

<u>राजकोट / Rajkot – 360 001</u> Tele Fax No. 0281 – 2477952/2441142Email: commrappl3-cexamd@nic.in

रजिस्टर्डडाकए.डी. द्वारा:-

DIN-20230564SX000061826F

अपील / फाइलसंख्या/ Appeal /File No.

मलआदेशसं / OIO No.

दिनांक/

Date 26-12-2022

GAPPL/COM/STP/982/2023

398/D/AC/2021-22

अपील आदेश संख्या(Order-In-Appeal No.):

#### RAJ-EXCUS-000-APP-133-2023

आदेश का दिनांक /

29.05.2023

जारी करने की तारीख /

Date of issue:

31.05.2023

Date of Order:

श्री शिव प्रताप सिंह, आयुक्त (अपील्स), राजकोट द्वारा पारित /

Passed by Shri Shiv Pratap Singh, Commissioner (Appeals), Rajkot.

अपर आयुक्त / संयुक्त आयुक्त / उपायुक्त / सहायक आयुक्त , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क / सेवाकर /वस्तु एवंसेवाकर , ग राजकोट / जामनगर / गांधीधाम। द्वारा उपरलिखित जारी मूल आदेश से सृजित: / Arising out of above mentioned OIO issued by Additional/Joint/Deputy/Assistant Commissioner, Central Excise/ST / GST, Rajkot / Jamnagar / Gandhidham:

अपीलकर्ता & प्रतिवादी का नाम एवं पता / Name & Address of the Appellant & Respondent :-

### M/s. Jignesh Ramjibhai Makwana, 2/Kailash/Laxmi Society, B/h Raj Nagar, Nana Mova, Rajkot-360004.

इस आदेश(अपील) से व्यथित कोई व्यक्ति निम्नलिखित तरीके में उपयुक्त प्राधिकारी / प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर कर सकता है।/ Any person aggrieved by this Order-in-Appeal may file an appeal to the appropriate authority in the following way.

सीमा शुल्क , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रति अपील,केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम , 1944 की धारा 35B के अंतर्गत एवं वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86 के अंतर्गत निम्नलिखि+त जगह की जा सकती है।/ (A)

Appeal to Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal under Section 35B of CEA, 1944 / Under Section 86 of the Finance Act, 1994 an appeal lies to:-

वर्गीकरण मूल्यांकन से सम्बन्धित सभी मामले सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण की विशेष पीठ, वेस्ट ब्लॉक नं 2, आर॰ के॰ पुरम, नई दिल्ली, को की जानी चाहिए।/ (i)

The special bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal of West Block No. 2, R.K. Puram, New Delhi in all matters relating to classification and valuation.

उपरोक्त परिच्छेद 1(a) में बताए गए अपीलों के अलावा शेष सभी अपीलें सीमा शुल्क,केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट) की पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका,,द्वितीय तल, बहुमाली भवन असार्वा अहमदाबाद- ३८००१६को की जानी चाहिए।/ (ii)

To the West regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at, 2<sup>nd</sup> Floor, Bhaumali Bhawan, Asarwa Ahmedabad-380016in case of appeals other than as mentioned in para- 1(a) above

अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील) नियमावली, 2001, के नियम 6 के अंतर्गत निर्धारित किए गये प्रपत्र EA-3 को चार प्रतियों में दर्ज किया जाना चाहिए। इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां उत्पाद शुल्क की माँग , ब्याज की माँग और लगाया जुर्माना, रुपए 5 लाख या उससे कम, 5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए तक अथवा 50 लाख रुपए से अधिक हैं तो क्रमशः 1,000/- रुपये ज्या निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संलग्न करें। निर्धारित शुल्क का भुगतान, संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक रजिस्टार के नाम से किसी भी सार्वजिनक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेखांकित बैंक ड्राप्ट द्वारा किया जाना चाहिए। संबंधित ड्राप्ट का भुगतान, बैंक की उस शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है। स्थगन आदेश (स्टे ऑर्डर) के लिए आवेदन-पत्र के साथ 500/- रुपए का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।/ (iii)

The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 / as prescribed under Rule 6 of Central Excise (Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against one which at least should be accompanied by a fee of Rs. 1,000/- Rs.5000/-, Rs.10,000/- where amount of duty demand/interest/penalty/refund is upto 5 Lac., 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asst. Registrar of branch of any nominated public sector bank of the place where the bench of any nominated public sector bank of the place where the bench of stay shall be accompanied by a fee of Rs. 500/-.

अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील, वित्त अधिनियम,1994की धारा 86(1) के अंतर्गत सेवाकर नियमवाली, 1994, के नियम 9(1) के तहत निर्धारित प्रपत्र S.T.-5में चार प्रतियों में की जा सकेगी एवं उसके साथ जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गयी हो, उसकी प्रति साथ में संलग्न करें (उनमें से एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) और इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां सेवाकर की माँग , ब्याज की माँग और लगाया गया जुर्माना, रुपए 5 लाख एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) और इनमें से कम से कम एक प्रति के अधिक है तो क्रमश: 1,000/- रुपये, 5,000/- रुपये अथवा 10,000/- या उससे कम,5 लाख रुपए यो 50 लाख रुपए तक अथवा 10,000/- रुपये अथवा 10,000/- रु (B)

The appeal under sub section (1) of Section 86 of the Finance Act, 1994, to the Appellate Tribunal Shall be filed in quadruplicate in Form S.T.5 as prescribed under Rule 9(1) of the Service Tax Rules, 1994, and Shall be accompanied by a copy of the order appealed against (one of which shall be certified copy) and should be accompanied by a fees of Rs. 1000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied of Rs. 5 Lakhs or less, Rs.5000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than five lakhs but not exceeding Rs. Fifty Lakhs, Rs.10,000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than fifty Lakhs rupees, in the form of crossed bank draft in favour of the Assistant Registrar of the bench of nominated Public Sector Bank of the place where the bench of Tribunal is situated. / Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs.500/-.

- वित्त अधिनियम,1994की धारा 86 की उप-धाराओं (2) एवं (2A) के अंतर्गत दर्ज की गयी अपील, सेवाकर नियमवाली, 1994, के नियम 9(2) एवं 9(2A) के तहत निर्धारित प्रपत्र S.T.-7 में की जा सकेगी एवं उसके साथ आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अथवा आयुक्त (अपील), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा पारित आदेश की प्रतियाँ संलग्न करें (उनमें से एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) और आयुक्त द्वारा सहायक आयुक्त अथवा उपायुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क / सेवाकर, को अपीलीय न्यायिकरण को आवेदन दर्ज करने का निर्देश देने वाले आदेश की प्रति भी साथ में संलग्न करनी होगी। / The appeal under sub section (2) and (2A) of the section 86 the Finance Act 1994, shall be filed in For ST.7 as prescribed under Rule 9 (2) &9(2A) of the Service Tax Rules, 1994 and shall be accompanied by a copy of order of Commissioner Central Excise or Commissioner, Central Excise (Appeals) (one of which shall be a certified copy) and copy of the order passed by the Commissioner authorizing the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Central Excise / Service Tax to file the appeal before the Appellate Tribunal. (i)
- सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय प्राधिकरण (सेस्टेट) के प्रति अपीलों के मामले में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 35 एफ के अंतर्गत, जो की वित्तीय अधिनियम, 1994 की धारा 83 के अंतर्गत सेवाकर को भी लागू की गई है, इस आदेश के प्रति अपीलीय प्राधिकरण में अपील करते समय उत्पाद शुल्क/सेवा कर मांग के 10 प्रतिशत (10%), जब मांग एवं जुर्माना विवादित है, या जुर्माना, जब केवल जुर्माना विवादित है, का भुगतान किया जाए, बशर्ते कि इस धारा के अंतर्गत जमा कि जाने वाली अपेक्षित देय राशि दस करोड़ रुपए से अधिक न हो।

  केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर के अंतर्गत "मांग किए गए शुल्क" मे निम्न शामिल है

  (i) धारा 11 डी के अंतर्गत रकम (ii)

(ii) सेनवेट जमा की ली गई गलत राशि (iii) सेनवेट जमा की ली गई गलत राशि (iii) सेनवेट जमा नियमावली के नियम 6 के अंतर्गत देय रकम – बशर्ते यह कि इस धारा के प्रावधान वित्तीय (सं° 2) अधिनियम 2014 के आरंभ से पूर्व किसी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन

्वशर्ते यह कि इस धारा के प्रावधान वित्तीय (सं॰ 2) अधिनयम 2014 के आरंभ से पूर्व किसी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन स्थगन अर्जी एवं अपील को लागू नहीं होगे।/
For an appeal to be filed before the CESTAT, under Section 35F of the Central Excise Act, 1944 which is also made applicable to Service Tax under Section 83 of the Finance Act, 1994, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute, provided the amount of pre-deposit payable would be subject to a ceiling of Rs. 10 Crores,

Under Central Excise and Service Tax, "Duty Demanded" shall include:

(i) amount determined under Section 11 D;
(ii) amount of erroneous Cenvat Credit taken;
(iii) amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules

- provided further that the provisions of this Section shall not apply to the stay application and appeals pending before any appellate authority prior to the commencement of the Finance (No.2) Act, 2014.

भारत सरकार कोपुनरीक्षण आवेदन :

Revision application to Government of India:
इस आदेश की पुनरीक्षण याचिका निम्नलिखित मामलो में,केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम,1994 की धारा 35EE के प्रथमपरंतुक के अंतर्गतअवर सचिव,
भारत सरकार, पुनरीक्षण आवेदन ईकाई,वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001, को किया
A revision application lies to the Unit Committee of the state of the s (C) A revision application lies to the Under Secretary, to the Government of India, Revision Application Unit, Ministry of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi-11000 I, under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35B ibid:

यदि माल के किसी नुकसान के मामले में, जहां नुकसान किसी माल को किसी कारखाने से भंडार गृह के पारगमन के दौरान या किसी अन्य कारखाने या फिर किसी एक भंडार गृह से दूसरे भंडार गृह पारगमन के दौरान, या किसी भंडार गृह में या भंडारण में माल के प्रसंस्करण के दौरान, किसी कारखाने या किसी भंडार गृह में माल के प्रसंस्करण के दौरान, किसी कारखाने या किसी शिंदा गृह में माल के प्रसंस्करण के दौरान, किसी कारखाने या किसी In case of any loss of goods, where the loss occurs in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse (i)

भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात कर रहे माल के विनिर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल पर भरी गई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के छुट (रिबेट) के मामले में, जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात की गयी है। / In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India. (ii)

यदि उत्पाद शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर, नेपाल या भूटान को माल निर्यात किया गया है। / In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty. (iii)

सुनिश्चित उत्पाद के उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो ड्यूटी क्रेडीट इस अधिनियम एवं इसके विभिन्न प्रावधानों के तहत मान्य की गई है और ऐसे आदेश जो आयुक्त (अपील) के द्वारा वित्त अधिनियम (न॰ 2),1998 की धारा 109 के द्वारा नियत की गई तारीख अथवा समायाविधि पर या बाद में पारित किए गए हैं।/
Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec. 109 of the Finance (No.2) Act, 1998. (iv)

उपरोक्त आवेदन की दो प्रतियां प्रपत्र संख्या EA-8 में, जो की केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) नियमावली,2001, के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट है, इस आदेश के संप्रेषण के 3 माह के अंतर्गत की जानी चाहिए। उपरोक्त आवेदन के साथ मूल आदेश व अपील आदेश की दो प्रतियां संलग्न की जानी चाहिए। साथ ही केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35-EE के तहत निर्धारित शुल्क की अदायगी के साक्ष्य के तौर पर TR-6 की प्रति संलग्न की जानी (v) नाहिए। / The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-In-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.

पुनरीक्षण आवेदन के साथ निम्नलिखित निर्धारित शुल्क की अदायगी की जानी चाहिए। जहाँ संलग्न रकम एक लाख रूपये या उससे कम हो तो रूपये 200/- का भुगतान किया जाए और यदि संलग्न रकम एक लाख रूपये से ज्यादा हो तो रूपये 1000 -/ का भुगतान किया जाए। The revision application shall be accompanied by a fee of Rs. 200/- where the amount involved in Rupees One Lac or less and Rs. 1000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac. (vi)

यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश है तो प्रत्येक मूल आदेश के लिए शुल्क का भुगतान, उपर्युक्त ढंग से किया जाना चाहिये। इस तथ्य के होते हुए भी की लिखा पढ़ी कार्य से बचने के लिए यथास्थिति अपीलीय नेयाधिकरण को एक अपील या केंद्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाता है। / In case, if the order covers various numbers of order in Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner, notwithstanding the fact that the one appeal to the Appellant Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filled to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lakh fee of Rs. 100/- for each. (D)

यथासंशोधित न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1975, के अनुसूची-I के अनुसार मूल आदेश एवं स्थगन आदेश की प्रति पर निर्धारित 6.50 रुपये का न्यायालय शुल्क टिकिट लगा होना चौहिए। / One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjudicating authority shall bear a court fee stamp of Rs.6.50 as prescribed under Schedule-I in terms of the Court Fee Act,1975, as amended. (E)

सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्य विधि) नियमावली, 1982 में वर्णित एवं अन्य संबन्धित मामलों को सम्मिलित करने वाले नियमों की और भी ध्यान आकर्षित किया जाता है। / Attention is also invited to the rules covering these and other related matters contained in the Customs, Excise and Service Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982. (F)

उच्च अपीलीय प्राधिकारी को अपील दाखिल करने से संबंधित व्यापक, विस्तृत और नवीनतम प्रावधानों के लिए, अपीलार्थी विभागीय वेबसाइट www.cbec.gov.in को देख सकते हैं।/ For the elaborate, detailed and latest provisions relating to filing of appeal to the higher appellate authority, the appellant may refer to the Departmental website www.cbec.gov.in (G)



# <u>:: अपील आदेश ::</u> :: ORDER-IN-APPEAL ::

M/s. Jignesh Ramjibhai Makwana, 'KAILASH', 2- Laxmi Society, Behind Raj Nagar Chowk, Nanamava Road, Rajkot, Gujarat 360004(hereinafter referred to as "Appellant") has filed present Appeal against Order-in-Original (OIO) No. 398/D/AC/2021-22 dated 26.12.2022 (hereinafter referred to as 'impugned order') passed by the Assistant Commissioner, Central GST, Division- I Rajkot (hereinafter referred to as 'adjudicating authority').

- The facts of the case, in brief, are that the Income Tax Department 2. provided data/ details of various Income Tax payers, who in their Income Tax Returns for financial year 2016-17 declared to have earned income by providing services classified under various sectors. The Income Tax Department also provided data of Form 26AS showing details of total amount paid/ credited under Section 194C, 194H, 194I & 194J of the Income Tax Act, 1961 in respect of various persons which depicted that such persons had earned income from providing services like contract, commission or brokerage, renting of movable/ immovable property, Technical or Professional service etc. The said data also contained the details of the Appellant who had not obtained Service Tax Registration under the Finance Act, 1994 (hereinafter referred to as 'the Act'). The jurisdictional office called for the information/ documents from appellant. No reply/ response was received from the appellant and the Service Tax was determined on the basis of data/ details provided by the Income Tax department and culminated into Show Cause Notice dated 06.10.2021 invoking extended period of 5 years proposing to demand Service Tax of Rs. 5,78,933/-, including all cesses under Section 73(1) of the Finance Act, 1994 (hereinafter referred to as 'the Act') with interest under Section 75 of the Act, and proposing to impose penalty under Section 77(1)(a), 77(1)(c), 77(2) and Section 78 of the Act.
- 3. The adjudicating authority vide the impugned order confirmed Service Tax demand of Rs. 5,78,933/- under Section 73(1) invoking extended period of 5 years along with interest under Section 75 of the Act. The adjudicating authority-imposed penalties of Rs. 10,000/- each under Section 77(1)(a), 77(1)(c) and Section 77(2) of the Act. The penalty of Rs. 5,78,933/- was also imposed upon the Appellant under Section 78 of the Act.
- 4. The Appellant has preferred the present appeal on 24.02.2023 on various grounds mainly as stated below:

The adjudicating authority has erred in confirming demand of Rs. 5,78,933/-under Section 73(1) of the Act, erred in not allowing the benefit of Notification No. 25/2012 dated 20.06.2012, erred in demand of interest u/s 75 of the Act, erred in demanding penalty u/s 77(1)(a), 77(1)(c), 77(2) and 78 of the Act.

- 5. Personal hearing in the matter was held on 03.05.2023 which was attended by Shri Bhaskar Joshi, Advocate, and submitted that the appellant provided road construction service for Morbi Municipality as sub contractor. The service is exempt vide Sr.No. 13(a) of Notification No. 25/2012. Copy of sub contract agreement, Profit & Loss Account, Balance Sheet, Income Tax return, Form 26AS, Ledger, Work orders and final bill is enclosed. He requested to set aside the Order-In-Original.
- 6. Appellant, vide submission dated 24.02.2023, has submitted that they are engaged in providing services vide sub contract of construction of CC Road under main contractor of M/s Chinmay Enterprise who got the construction from Morbi Nagar Palika. Services provided by way of construction of road For Morbi Nagar Palika is covered under exemption Notification No. 25/2012 dated 20.06.2012 at Sr. No. 13(a). Their service, being falling under negative list, service tax is not leviable. Therefore, requested to set aside the impugned order and allow the appeal.
- 7. I have carefully examined the show cause notice, impugned order, appeal memorandum and written submission of the Appellant. The issue to be decided in the present appeal is whether amount reflected in data of Income Tax in respect of appellant is taxable or otherwise. Adjudicating Authority in the present case, due to absence of proper defence reply, submission and supporting documents by the appellant was left with no way but to decide the issue on the basis of available records and thus considering the amount appearing in Income Tax return of the appellant as taxable and confirmed the demand of Service Tax of Rs. 5,78,933/- with interest and penalties.
- Regarding amount of Rs. 38,59,550/-, considered as taxable with reason unexplained income, appellant, vide their written submission, has provided copies of work orders, 26AS, Audit reports etc., in support of their claim considering the work contract as exempted as per entry No. 13(a) of Mega Exemption Notification No. 25/2012 dated 20.06.2012. Details as under:

Table- 'A'

2016-17

Sr. No.	Particular of work	Amount(Rs.)	Exempt under entry No. of Notification No. 25/2012
1.	Providing construction of CC road to Morbi Nagar Palika through main contractor M/s Chinmay Enterprise	37,90,550/-	13(a)
2.	Providing construction service to M/s Kunal Structure (India) Private Limited	69,000/-	~
	Total (held as taxable value in impugned order)	38,59,550/-	

7.2 Going through Profit & Loss Account, Form 26AS and Income Tax Return of the appellant, I find that the amount of Rs. 38,59,550/- held as taxable in impugned order is construction income, appellant has incurred expenditure of Labour expense, salary expense, Material expense, etc. While going through other supporting documents viz. agreement for sub contract, copies of retail invoice & purchase invoice of material. I observed that appellant has provided construction service through sub contract to Morbi Nagar Palika. Accordingly, the service provided by the appellant is falling under list of exempted services as per Entry No. 13(a) of exemption Notification No. 25/2012 dated 20.06.2012, relevant portion of Notification No. 25/2012 is reproduced hereunder:

- "13. Services provided by way of construction, erection, commissioning, installation, completion, fitting out, repair, maintenance, renovation, or alteration of,-
- (a) a road, bridge, tunnel, or terminal for road transportation for use by general public;"
- 7.2.1 Therefore, in view of above, I find that the appellant being person providing service by way of construction of road for use by general public, is covered under the exempted service list and income of Rs. 37,90,550/- earned from it is not taxable. Hence, appellant is not liable to pay Service Tax. As such, I hold that demand of service tax is not sustainable.
- 7.3 Amount of remaining income of Rs. 69,000/- (at sr. no. 2 of Table-'A' at Para-9) Rs. 38,59,550/- (amount held as taxable in impugned order) Rs. 37,90,550/- (exempted income) = Rs. 69,000/-) is below threshold limit of Rs. 10 Lakhs. As per provisions of Notification No. 33/2012-Service Tax dated 20.06.2012, aggregate value of taxable services below 10 lakhs rupees is exempted from the whole of the Service Tax during a financial year. Relevant portion of Notification No. 33/2012-ST dated 20.06.2012 is reproduced below:

NOTIFICATION NO 33/2012-ST, Dated: June 20, 2012

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 93 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994) (hereinafter referred to as the said Finance Act), and in supersession of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) notification No. 6/2005-Service Tax, dated the 1st March, 2005, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide G.S.R. number 140(E), dated the 1st March, 2005, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts taxable services of aggregate value not exceeding ten lakh rupees in any financial year from the whole of the service tax leviable thereon under section 66B of the said Finance Act:

Explanation .- For the purposes of this notification,-

(A) ......
(B) "aggregate value" means the sum total of value of taxable services charged in the first consecutive invoices issued during a financial year but does not include value charged in invoices issued towards such services which are exempt from whole of service tax leviable thereon under section 66B of the said Finance Act under any other notification."

Appellant has also submitted financial documents of F.Y. 2015-16 therein the income excluding interest income is below threshold limit,

Therefore, benefit of threshold limit as per Notification No. 33/2012-ST dated 20.06.2012 is available to the taxable amount for the successive Financial Year i.e. 2016-17 (relevant period). Thus, income of Rs. 2,70,960/- is exempted from levy of Service Tax. Therefore, demand of Service Tax on this income is not sustainable.

- 8. I, therefore, set aside the confirmation of Service Tax demand of Rs. 2,70,960/-. Since, the demand is set aside, recovery of interest under Section 75 and imposition of penalty under Section 77 and 78 are also required to be set aside and I order accordingly.
- 9. In view of the above discussion and findings, I set aside the impugned order and allow the appeal.
- 10. अपीलकरता दवारा दर्ज की गई अपील का निपटारा उपरोक्त तरीके से किया जाता है।
- 10. The appeal filed by the Appellant is disposed off as above.

सत्यापित / Attested

बी. ओस. राजा / B. S. RANA अधीयक / Cup stintendent के व एवं सेवा कर अधील्स, राजकोट

के. व. एवं सेवा कर अपील्स, राजकोद CGST Appeals, Rajkot 29-5-23

(शिव प्रताप सिंह) (Shiv Pratap Singh) आयुक्त (अपील)

Commissioner (Appeals)

By R.P.A.D.

To, M/s. Jignesh Ramjibhai Makwana, 'KAILASH', 2- Laxmi Society, Behind Raj Nagar Chowk, Nanamava Road, Rajkot, Gujarat 360004. सेवा में,

मे॰ जिग्नेश रामजीभाई मकवाना, ''कैलाश'', 2- लक्ष्मी सोसाइटी, राज नगर चौक के पीछे, नानामवा रोड, राजकोट, गुजरात -360004।

## प्रतिलिपि :-

- 1) मुख्य आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, गुजरात क्षेत्र, अहमदाबाद को जानकारी हेतु।
- 2) प्रधान आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, राजकोट आयुक्तालय, को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3) अपर/सयुंक्त आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, राजकोट को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 4) सहायक आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मण्डल-I राजकोट को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 5) गार्ड फाइल।

